सेक्टर 8 के ईएसआई अस्पताल को मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जाये- मज़दूर नेता

फ़रीदाबाद (म.मो.) गतांक में सेक्टर 8 स्थित ईएसआई अस्पताल को लेकर मज़दूर मोर्चा ने जो खबर प्रकाशित की थी उसे लेकर विभिन्न मज़दूर संगठनों की ओर से गंभीर प्रतिक्रियाएं सामने आई है। इन्कलाबी मज़दूर केन्द्र के संजय मौर्य ने मज़दूर मोर्चा कार्यालय आकर बताया कि जब हर छोटे-मोटे इलाज के लिये तमाम मज़दूरों को इस अस्पताल द्वारा ईएसआई मेडिकल कॉलेज की ओर धकेल दिया जाता है तो इस अस्पताल की जरूरत ही क्या है ?

विदित है कि ज़िले की अधिकांश डिस्पेंसरियां इसी सेक्टर 8 वाले अस्पताल से जुड़ी हुई हों। इसका मतलब यह होता है कि मरीज़ पहले अपनी डिस्पेंसरी में जायेगा जो उसे सीधे मेडिकल कॉलेज रेफ़र न करके सेक्टर 8 वाले अस्पताल को रेफ़र करती हैं जहां न पर्याप्त डॉक्टर हैं न स्टाफ़ और न ही आवश्यक दवायें एवं उपकरण आदि। ऑपरेशन थियेटर को तो वर्षों से ताला लगा पड़ा है। और तो और रैबीज (कुत्ता काटे) के इन्जेक्शन तक के लिये मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। जब हर छोटे-मोटे काम मेडिकल कॉलेज से ही होने हैं तो इस अस्पताल को भी सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज से क्यों नहीं जोड़ दिया जाता ?

हिन्द मज़दूर सभा के ज़िला महासचिव आरडी यादव का कहना है कि बीते 40 साल में उन्होंने इस अस्पताल का तमाशा भली-भांति अपनी आंखों से देख लिया है। उनकी समझ में यह बात अच्छी तरह आ गई है कि हरियाणा सरकार की नीयत ही इस अस्पताल को चलाने की कभी रही नहीं। इसी लिये 10 एकड़ के प्लॉट में 200 बिस्तरों के बने इस अस्पताल का सत्यानाश पीट कर रख दिया है। यादव के मुताबिक इस अस्पताल के लिये उस वक्त बनाया गया चार मेगावाट का बिजली घर बेहतरीन किस्म का है, लेकिन आज उसकी कुल क्षमता का आधा भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। उनके मुताबिक इस अस्पताल के जीर्णोद्धार पर 12 करोड़ रुपये खर्च करना पानी में बहाने जैसा होगा।

आरडी यादव ने मज़दूर मोर्चा में छपे दो ड्राइवरों द्वारा चलाये जाने वाले वाहन वाले जुमले पर चुटकी लेते हुये कहा कि इस तरह का वाहन कभी भी अपने गणतब्य पर नहीं पहुंच सकता, इसे तो बीच रास्ते

संजय मौर्या

आरडी यादव

दुर्घटनाग्रस्त होना ही होना है। समझ नहीं आता कि जब आठ रुपये में से सात रुपये ईएसआई कार्पोरेशन ने खर्च करने हैं तो मात्र एक रुपये के लिये यह चौधराहट हरियाणा सरकार को क्यों सौंप रखी है ? कर्पोरेशन जहां सात रुपये खर्च कर रही है वहां आठ भी कर सकती है। इतना ही नहीं उक्त सात रुपयों के अलावा अस्पतालों व डिस्पेंसरियों की बिल्डिंगों के निर्माण एवं रख-रखाव, यहां तक कि फ़र्नीचर व कई अन्य प्रकार के खर्चे भी कार्पोरेशन द्वारा ही वहन किये जाते हैं।

इन खर्चों को लेकर अस्पतालों व कार्पोरेशन के बीच सदैव तना-तनी बनी रहती है। बिल्डिंगों का सत्यानाश इसलिये हो जाता है कि इनकी देख-भाल का जिम्मा कार्पोरेशन का है। इस पर कार्पोरेशन वाले कहते हैं कि उन्हें कोई बताये तभी तो वे मुरम्मत आदि का काम करायेंगे। दूसरी ओर बिल्डिंगों में बैठे हरियाणा सरकार के अधिकारी कहते हैं कि वे बार-बार कार्पोरेशन को लिख-लिख कर थक गये हैं लेकिन इनकी कोई सुनता ही नहीं है। इसी तू-तू में-में, में सेक्टर सात डिस्पेंसरी खंडहर बन चुकी है और यह अस्पताल भी लगभग खंडहर बन चुका है।

उक्त नेताओं का यह भी तर्क है कि जब सनफ्लैग अस्पताल को खरीदने की बात कार्पोरेशन सोच सकती है तो अपने इसी अस्पताल को अधिग्रहित करने की बात क्यों नहीं करती ? गौरतलब है कि एनएच तीन वाला अस्पताल कार्पोरेशन के हवाले करते वक्त हरियाणा सरकार को बड़ा दर्द हुआ था। बेशक वह अस्पताल हरियाणा सरकार से चल नहीं पा रहा था, तो मज़दूरों की वहां भयंकर दुर्दशा होती थी। कैजुअल्टी में कोई मरीज़ रात काट नहीं सकता था। हालात ऐसे थे कि 200 बेड के अस्पताल में मजबूरी के मारे 100-150 मरीज़ ही दाखिल होते थे। वहीं आज 500-600 बेड सदैव भरे रहते हैं।

ऐसा ही दर्द सेक्टर आठ का अस्पताल छोड़ने से हरियाणा सरकार को होना निश्चित है। वास्तव में यह दर्द मुख्यत: उस डायरेक्टर को होता है जिसके आधीन ईएसआई स्वास्थ्य सेवायें चलती हैं। उस श्रम मंत्री को भी तकलीफ़ हो सकती है जिसके आदेश पर राज्य भर की तमाम डिस्पेंसरियों के स्टाफ़ हिसार स्थित एक नकली से कोविड अस्पताल में लाकर बैठा दिया जाय।

इन लोगों को ईएसआई कवर्ड उन 25-30 लाख मज़दूरों से कोई लेना-देना नहीं जिनको ईएसआई से चिकित्सा सुविधायें चाहियें; इनको तो केवल अपनी चौधर से मतलब है। यही लोग यदि चाहें तो ईएसआई चिकित्सा सेवाओं को बहुत ही बेहतरीन ढंग से चला सकते हैं। परन्तु न तो कभी इनकी, ऐसा करने की इच्छा रही न ही नीयत, यानी कि न तो खुद कुछ करेंगे और न किसी दूसरे को करने देंगे।

भूल चुके मंझावली पुल की याद फ़िर ताज़ा करा दी 'मज़दूर मोर्चा' ने

फ़रीदाबाद (म.मो.) 15-21 अगस्त के अंक में 'मज़दूर मोर्चा' ने मंझावली स्थित यमुना पुल की सातवीं वर्षगांठ मनाते हुए इसका शिलान्यास करने वाले मंत्रियों को शर्मशार किया था। वैसे तो इन मोटी चमड़ी वाले नेताओं का शर्म से कोई ताल्लुक होता नहीं, परन्तु फ़िर भी इन बयानवीरों ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते से निकाल कर बयान देने तो शुरू किये, चाहे झूठे ही हो।

इसी सप्ताह अखबारों में छपवाया गया है कि पुल तक पहुंच सड़क बनाने के लिये किसानों से ज़मीन खरीदने की बात चल रही है। वैसे इस तरह की बात चलने व इसके लिये कमेटी गठित करने सम्बन्धी बयान केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर कई बार दे चुके हैं। इसके अलावा पुल के निर्माण कार्य पूरा होने की डेडलाईन जनवरी 2022 भी घोषित कर दी गयी है। इस तरह की डेडलाईन पहले भी कई बार घोषित की जा चुकी हैं। सबसे पहली बार आधारशिला रखते वक्त केन्द्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने यह दो वर्ष रखी थी। 'मज़दूर मोर्चा' ने इन बयानवीरों की हकीकत को समझते हुए उसी वक्त लिख दिया था कि ये दो वर्ष में पुल चालू करने की बात करते हैं, इतने समय में यदि ये लोग डीपीआर भी बना दें तो बहुत बड़ी बात होगी; वही हुआ भी दो साल में पुल तो क्या डीपीआर, जो एक काग़जी कार्यवाही होती है, तक नहीं बना सके।

नई डेडलाईन घोषित करते वक्त बयानवीर नेता यह राग अलापना नहीं भूले कि पुल के बन जाने से नौएडा जाना कितना आसान हो जायेगा, कहां-कहां से आनेवालों को दिल्ली में घुसे बगैर नोयडा जाने से कितनी बचत होगी। अरे बयानवीरों इस होने वाली संभावित बचत का तो सब को पता है, यह क्यों नहीं बताते कि हमारी काहिली एवं हरामखोरी से अब तक, दिल्ली का चक्कर लगा कर नौयडा जाने वाले कितने अरबों रुपये का घाटा उठा चुके है और पर्यावरण को जो हानी हुई वह अलग से।

बेगानी शादी में अब्दुला दीवाना

करीब दो सप्ताह पूर्व एनआईटी के कांग्रेसी विधायक भी अपने नम्बर बनाने के लिए केन्द्रीय मंत्री नीतिन गडकरी से मिलने दिल्ली जा पहुंचे। इनके पास करने-धरने को तो कुछ विशेष होता नहीं तो खाली बैठे सोचा होगा कि चलो नीतिन जी से मिल कर मंझावली पुल के निर्माण में कुछ योगदान ही कर आयें। जैसा कि भास्कर में छपा है, इन्होंने पुल के न बनने से दिल्ली के आश्रम तक पहुंचने में, जाम के कारण होने वाली कठिनाई का उल्लेख किया। उनकी इस मूर्खतापूर्ण बात को सुन कर हैरान हैरान तो जरूर हुए होंगे परन्तु परेशान नहीं क्योंकि उन्होंने विधायक महोदय के दिमागी स्तर का सही-सही आंकलन करते हुए उन्हें चाय-पानी पिला रूकसत कर दिया।

भाजपा डाल-डाल तो राव इन्द्रजीत पात-पात

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

किसान आन्दोलन के चलते आज पूरे हरियाणा में भाजपा नेताओं को कहीं पांव टिकाने की थोड़ी बहुत जगह है भी तो वह अहीरवाल है। यहां से करीब 11 विधानसभा सीटों पर भाजपा अपना भविष्य उज्ज्वल देख पा रही है। लेकिन इस क्षेत्र में भाजपा की सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं केन्द्रीय राज्यमंत्री राव इन्द्रजीत। इस क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत करने के इरादे से 2014 में भाजपा ने राव इन्द्रजीत को कांग्रेस से आयात किया था। उस समय राव साहब कांग्रेस आला कमान से इस लिये खफ़ा थे कि पार्टी ने उन्हें न तो हरियाणा का सीएम बनाया और केन्द्र में भी बनाया तो मात्र राज्यमंत्री, वह भी बेकार से (विदेश) मंत्रालय का।

भाजपा ने राव साहब के असन्तोष को कैश करने का इसे एक बढ़िया अवसर समझा। लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद भाजपा ने उन्हें तुरन्त केन्द्रीय राज्यमंत्री बना दिया, जो कुछ कांग्रेस ने दे रखा था, वही दिया; लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया। इसी आश्वासन को लेकर

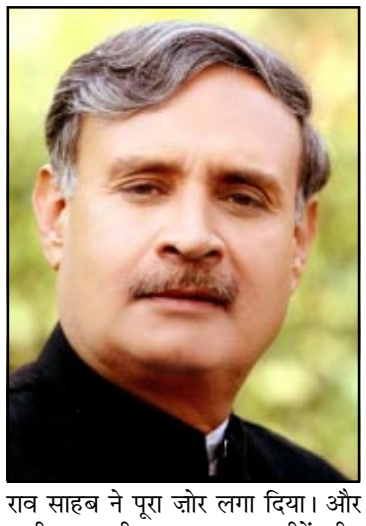

राव साहब ने पूरा ज़ोर लगा दिया। और अहीरवाल की लगभग तमाम सीटें जीत कर भाजपा की झोली में डाल दी लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। भाजपा की मक्कारी यह थी कि उसने कैप्टन अभिमन्यु सहित कई नेताओं को इसी तरह का आश्वासन दे रखा था। जिस क्षेत्र में भी भाजपा की चुनावी रैली होती, वहां की सीटें जीतने के उद्देश्य से वहीं के किसी प्रत्याशी को आगामी मुख्यमंत्री बता देती थी। लेकिन भाजपा किसी भी कद्दावर राजनीतिज्ञ को तो मुख्यमंत्री बनाने वाली थी नहीं, उसे तो खट्टर जैसे चड्ढीधारी प्रचारक को यह पद देना था जो सदैव उनके खूंटे से बंधा रहे।

जाहिर है, अन्य भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की तरह रावसाहब भी मन मसोस कर रह गये। अंधभक्तों की मोदी लहर के चलते उन्होंने चुपचाप रह कर मौके का इन्तज़ार करना ही बेहतर समझा। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वे अपनी बेटी के लिये भाजपा टिकट तथा अपने लिये विधानसभा का टिकट चाहते थे, परन्तु भाजपा उन्हें केवल लोकसभा का टिकट वह भी भिवानी-नरनौन से देना चाहती थी। राव साहब ने सख्त तेंवर दिखाते हुये इससे इन्कार कर दिया तो भाजपा को झुकना पड़ा और उनकी गुड़गांव सीट बरकरार रखी। वे चुनाव जीत गये लेकिन मंत्रीमंडल में उनका कद वही बौने का बना रहा; बाद में विधानसभा चुनाव के उपरांत '75 पार' का नारा देने वाली पार्टी 40 का आंकड़ा भी तमाम तरह की हेरा-फेरी व बेइमानियों के माध्यम से ही छू पाई। इसके बावजूद पुन: खट्टर को ही मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया। इस बीच कैप्टेन अभिमन्यु जैसे मुख्यमंत्री पद के तमाम दावेदार मैदान से खारिज हो चुके थे। अब केवल राव साहब ही एकमात्र दावेदार बचे थे, परन्तु इनके पास संघ की वफ़ादारी का प्रमाणपत्र नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिये इनकी जिज्ञासा एवं जोड़-तोड़ को देखते हुये भाजपा इनके प्रति सदैव सशंकित ही रही।

इन्हीं सब कारणों के चलते भाजपा ने अहीरवाल से इनका सफ़ाया करने के लिये एक नया मोहरा भूपेन्द्र यादव के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया। उन्हें पहले तो राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनाया गया तथा बीते माह केन्द्र में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। उनका कद ऊंचा करने के लिये उन्हें गत वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव में भी प्रोजेक्ट किया गया। उनके गांव जमालपुर (रिवाड़ी) में अमितशाह का जाना, उनकी तिरंगा यात्राओं एवं रैलियों को मुख्यमंत्री से भी अधिक भव्य बनाना, सब ऐसी कवायदें रही जिनसे उन्हें राव साहब से ऊंचा करके दिखाया जाय।

परन्तु राव इन्द्रजीत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। जिस जमाने में भाजपा के गुजराती मालिक चाय मूंगफ़ली बेचा करते थे इनके बाप-दादा राज चलाया करते थे। वह बात अलग है कि साम्प्रदायिकता के घोड़े पर सवार होकर घूर्तता की तमाम सीमायें लांघते हुए इन्होंने वक्की तौर पर तमाम राजनीतिज्ञों को पछाड़ दिया। भाजपा डाल-डाल तो राव इन्द्रजीत पात-पात की कहावत चरिचार्थ करते हुये कांग्रेस के साथ अपनी निकटता बढ़ाते रहे।

भूपेन्द्र हुड्डा, शैलजा से लेकर गांधी परिवार तक उनकी पैंठ बढने लगी। इतना ही नहीं ओम प्रकाश चौटाला भी इनके साथ गठबंधन के तखमीने लगा रहे हैं। बेशक 2024 अभी दूर है, उस वक्त राव साहब का ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो कहना जल्दबाज़ी होगा; लेकिन इतना तो तय है कि वे भाजपा तो टिकने वाले हैं नहीं। इसका परिणाम यह होगा कि जिस अहीरवाल के भरोसे भाजपा हरियाणा में टिक पाने का ख्वाब देख रही है, वह जरूर नष्ट हो जायेगा और भाजपा फ़िर से आ जायेगी अपनी पुरानी व असली औकात में जब इसके विधायकों की संख्या दहाई का आंकड़ा भी छू नहीं पाती थी।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06